भीनमाल को जिला नहीं बनाने के विरोध में सोमवार को अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक बंद रखा गया। बंद के अलावा स्थानीय लोगों ने कई स्थानों एवं क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन भी किया। बंद का पूरे क्षेत्र में व्यापक असर देखा गया, क्योंकि इस बंद का यहां की जनता एवं कारोबारियों ने स्वेच्छा से सहयोग एवं पूर्ण समर्थन दिया।

भीनमाल में भी जिला बनाओ आंदोलन ने जोर पकड़ा, सोमवार को पूरा शहर बंद रहा

सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से बाजार, प्रतिष्ठान बंद रखे

- **पहली बार भीनमाल में भाजपा व कांग्रेस के लोगों ने एक साथ मिलकर धरना दिया।**
- **पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भीनमाल के लोगों की भावनाओं को सोनिया गांधी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।**
- **क्षेत्र के वर्तमान कांग्रेस के विधायक पूराराम चौधरी और पूर्व विधायक समरजीत सिंह ने कहा कि, भीनमाल को जिला बनाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।**

भीनमाल, 20 मार्च (निसं)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 19 जिलों की घोषणा के दौरान जालोर जिले के भीनमाल को अलग जिला नहीं बनाने पर आक्रोशित भीनमाल की जनता एवं व्यापारियों ने सोमवार को सम्पूर्ण बंद रखा। बन्द को स्थानीय नागरिकों ने अभूतपूर्व समर्थन देकर इसे शानदार सफल बना दिया।

बन्द के दौरान लोगों को चाय, बीडी, नास्ता, सब्जी के साथ कुछ भी नसीब नहीं हुआ। यहां के व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रख कर कार्यक्रम में भाग लिया। लोगों में चर्चा थी कि, भीनमाल को जिला नहीं बनाने के लिए हमारे जन प्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण हम सब भुगत रहे हैं। धरना स्थल पर लोगों ने भयंकर रूप से रोष प्रकट कर नेताओं को इसके लिए दोषी करार दिया। उनका कहना था कि, अगर समय रहते इस मांग की ओर ध्यान दिया गया होता तो आज यह नौबत नही आती।

धरना स्थल पर मौजूद लोगों को सम्बोधित करते हुए पूर्व विधायक डॉ. समरजीत सिंह ने कहा कि भीनमाल नगरवासियों की भावनाओं को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का फोन आया था, उन्होंने भीनमाल क्षेत्र की भावनाओं को सोनिया गांधी तक पहुंचाने का विश्वास दिलाया। उन्होंने उनकी भावनाओं को सीएम अशोक गहलोत तक पहुँचाने की भी बात कही।

पूर्व विधायक ने कहा कि, लगातार हार के बावजूद भीनमाल के हित में राजनीति से ऊपर उठकर संघर्षरत रहने का विश्वास दिलाया।

वर्तमान विधायक पूराराम चौधरी ने कहा कि, जब तक भीनमाल जिला नहीं बनेगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। चौधरी ने कहा कि भले उन्हें विधानसभा व राजनीति से इस्तीफा देना पड़े तो भी वे पिछे नहीं हटेंगे। विधायक ने कहा कि भीनमाल के साथ धोखा हुआ है, इसके विरुद्ध संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने धरने को अनवरत जारी रखने का आव्हान किया।

धरना स्थल पर कांग्रेस एवं भाजपा के कई नेताओं ने अपने विचार व्यक्त कर बताया कि, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं देकर इस मामले को हल्के में ही लिया। लोगों के साथ सभी पार्टियों के नेता भी इस मामले में गुमराह बने रहे। उन्हें आशा थी कि भीनमाल को जरूर जिला घोषित किया जायेगा। भीनमाल जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में रानीवाडा, जसवंतपुरा, बागोडा, भीनमाल सहित आस-पास के अनेक क्षेत्र के नागरिक बंधुओं, प्रबुद्धजनों, स्वयं सेवी संस्थाओं, ट्रस्टों, सामाजिक संगठनों व जन प्रतिनिधियों की ओर से ज्ञापन उपखंड अधिकारी पूनम चौधरी को सौंपा गया।

ज्ञापन देते समय पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. समरजीत सिंह, भाजपा विधायक पूराराम चौधरी, धुखाराम राजपुरोहित, संजीव माथुर, शैतानसिंह भाटी, भरत सिंह भोजाणी, अशोक सिंह ओपावत, सत्यवान सिंह राजपुरोहित, नरिंगाराम चौधरी, माणकमल भंडारी, संदीप देसाई, सांवलाराम देवासी, बाबुलाल चौधरी, शंभुसिंह राठौड़, श्रवण सिंह राव, नवलकिशोर राठी, ओमप्रकाश महेश्वरी, नरेश अग्रवाल इत्यादि मौजूद रहे। कार्यालय के बाहर हजारों की संख्या में लोग जमा होकर अपनी मांग पर आक्रोशित नजर आए।

भीनमाल में यह पहला मौका था जब कांग्रेस और भाजपा के नेता एक साथ धरने पर बैठे थे।

धरने में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉ. समरजीत सिंह राठौड़ एवं भाजपा के विधायक पूराराम चौधरी सहित भाजपा व कांग्रेस के नेता पहली बार एक साथ एक जाजम पर मिलकर भीनमाल को जिला बनाने के लिए धरना दे रहे थे।

'असली जादूगर तो नीली छतरी वाला है, बाकी सब हाथ की सफाई है'

पायलट ने यह भी कहा कि, राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है, जब हारते हैं तो इतना लंबा हारते हैं कि, वो गैप लंबा होता है

- **नरेन्द्र मोदी को चुनाव में हराने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, कौनसा ऐसा नेता है, जिसे चुनाव में पराजित नहीं कर सकते।**

नई दिल्ली, 20 मार्च (का.प्र.)। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नई दिल्ली में एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि 'राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना पार्टी का फैसला था और हम सबकी इसमें सहमति थी। वैसे भी हमारे समाज मे उम्र का एक प्रीमियम होता है।

पायलट ने कहा कि राजस्थान में हर पांच साल मे सरकार बदल जाती है। उस दौरान जब हारते हैं तो इतना लंबा हारते हैं कि वो गैप लंबा हो जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि उनको हार का डर नहीं लग रहा है, लेकिन इतिहास से सीखना तो पडेगा। मैंने अपनी पार्टी में कुछ सुझाव दिए थे, ताकि ये पुनरावृति नहीं हो। बाकी स्टेट में कांग्रेस सरकार रिपीट हुई हैं,इसलिए राजस्थान में सबको मिलकर काम करना होगा, अभी बहुत काम करने की जरूरत है।

सचिन पायलट ने कहा कि 'पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हर स्टेट में अलग रणनीति होती है। हमने पांच साल मेहनत करके राजस्थान में चुनाव लडा, अंत में पार्टी ने जो निर्णय लिया, उसे सभी ने स्वीकार किया। पायलट ने कहा कि 'आप मुझ पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि मैंने ऐसे शब्दों का उपयोग किया। इसलिए शब्दों का चयन महत्वपूर्ण होता है। बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए उन्होंने कहा कि जिसने इस तरह की बात की बोली, ये उससे पूछना चाहिए। हमारी संस्कृति है कि जो बड़े लोग हैं, चाहे किसी दल के हो, हमने मान-सम्मान दिया। पायलट ने कहा कि वो चाहते थे कि किसी इंसान को बुरा नहीं लगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए नाकारा- निकम्मा जैसे शब्दों का प्रयोग किया था।

पायलट ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि असली जादूगर तो नीली छतरी वाला है, बाकी सब हाथ की सफाई है। पायलट ने कहा कि जनभावना का एक ही टैस्ट है और वो है बैलेट बॉक्स। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में हम लोग बेहतर प्रदर्शन करें। कौन कब किस पद पर बैठेगा, ये पार्टी का निर्णय होता है। सोनिया गांधी ने पिछले साल पर्यवेक्षक भेजे थे, मगर विधायको की बैठक नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि मैं पद की राजनीति नहीं करता। पार्टी ने बहुत सारे पद दिए, पार्टी का शुक्रगुजार रहता हूं, पद की कोई कमी नहीं रही।

इसी के साथ देश में लोकतंत्र पर खतरा होने के राहुल गांधी के बयान पर उठ रहे विवाद पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा कि 'पिछले 7-8 सालों में ऐसे हालात बन रहे हैं, जिससे ये बात उठ रही है। अगर लोगों को अपनी बात रखने से भय पैदा होता है, गैर-जरूरी दवाब पैदा होता है, तो जाहिर है कि लोकतंत्र पर खतरे की बात होगी।

पायलट ने कहा कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, तो वो देश के खिलाफ नही बोल रहे हैं। देश में लोकतंत्र स्वस्थ रहे, इसके लिए लोगों को खुलकर बोलना जरूरी है। पायलट ने कहा कि अगर लोकतंत्र स्वस्थ नहीं रहेगा, तो पिछले कुछ समय में देश की सस्थाएं कमजोर पड़ जाएंगी। पायलट ने कहा कि 'कांग्रेस खतरे में है या नहीं, ये अलग बात है, मगर लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में हमेशा कायम रहना चाहिए। इसके लिए लगातार सावधान और सचेत रहना है। वैसे भी कई इंडेक्स मे भारत की रैंक गिरती जा रही है, फ्रीडम मे कमी आई है। इसके लिए आत्मचिंतन करना चाहिए,क्योंकि देश में कई सरकारें आईं हैं और आगे भी आती रहेंगी।

पीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। कौन सा ऐसा नेता है, जिसे चुनाव मे पराजित नहीं कर सकते हैं। हिमाचल मे चुनाव था, सब बडे नेता गए, मगर वहां सरकार कांग्रेस की बनी। पायलट ने कहा कि देश का मतदाता ये नहीं चाहता कि नेता ये सोचे कि वोट उसकी जेब में है। मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, मुद्दे धार्मिक व जज्बाती नहीं होने चाहिए।

पायलट ने कहा कि आज मंत्री खड़े होकर संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। मंत्री खुद बाधा डाल रहे हैं। ये सब लोग देख रहे हैं, सही समय पर लोग जवाब देंगे।

सत्तारूढ़...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की तरफ से हो रहा था लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन को काम करने के वास्ते बातचीत करने के लिये केवल विपक्षी नेताओं को ही बुलाने का निर्णय लिया।

राहुल गांधी सोमवार को चुनाव प्रचार के सिलसिले में दिल्ली से बाहर, कर्नाटक में थे, उनकी पार्टी के सांसदों ने जोर देते हुये कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है जिसके लिये माफी माँगी जाये।

शनिवार को, विदेशी मामलों से संबंधित संसदीय समिति की मीटिंग में राहुल गांधी को अवसर मिल गया था जिसका उपयोग करते हुये, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिये कहीं भी विदेशी मदद नहीं माँगी।

उन्होंने समिति में मौजूद दो भाजपा सांसदों से कहा था कि वे उनके खिलाफ फैलाई जा रही इस झूठी अफवाह को रोकें।

विंड मिल से टकरा कर कई दुर्लभ पक्षियों की मौत

- **पर्यावरण विशेषज्ञों ने इनकी पहचान स्टैपी ईगल, हिमालयन वल्चर के रूप में की है।**
- **स्थानीय लोगों ने बताया कि, गांवों में जो तालाब है वहां पानी पीने के लिए पक्षी आते हैं और आस-पास लगी विंड मिल्स के पंखों से टकराकर मर जाते हैं।**

जैसलमेर, 20 मार्च (नि.सं.)। जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील के छोड़िया व लखमणा गांवों के पास मौजूद पवन चक्कियों (विंड मिल्स) के पंखों से टकराकर कई प्रजातियों के गिद्धों व बाजों मौत हो गई। सोमवार को स्थानीय चरवाहों की सूचना पर पर्यावरण विशेषज्ञों ने इन शवों को देखा।

पर्यावरण विशेषज्ञ राधेश्याम पेमानी विश्नोई और पार्थ जगाणी पक्षियों की पहचान स्टेपी ईगल, हिमालयन गिद्ध और सिनेरियस गिद्ध के रूप में की। सुमेर सिंह भाटी सांवता ने बताया की श्री देगराय मन्दिर ओरण के पीछे जो गांव है वहां कुछ पुराने तालाब हैं, जिनमें पानी पीने के लिये पक्षी आते हैं और आसपास मौजूद पवन चक्कियों के पंखों से टकराकर मारे जाते हैं।

चंबल नदी में डूबे दो बालकों के शव और मिले, मृतकों की संख्या 7 हुई

करौली, 20 मार्च (नि.स.)। मंडरायल के रोधई घाट पर चंबल नदी में 17 पद यात्रियों के डूबने के मामले में लगातार तीसरे दिन लापता की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। शेष दो शव सोमवार को चंबल नदी से तलाशी के दौरान बाहर निकाले गए। सुबह करीब 10 बजे बृजमोहन (17) तथा दोपहर करीब 3 बजे लव कुश (12) का शव चंबल से निकाला। इसके बाद सर्च ऑपरेशन समाप्त हो गया।

घटना में शनिवार को 2 लोगों के शव चम्बल नदी में मिले थे। जबकि 5 लापता हो गए और 10 को सुरक्षित बचा लिया था। रविवार को

- **शनिवार को हुई इस घटना में मध्य प्रदेश के 17 जने कैलादेवी के दर्शन करने आ रहे थे तथा चंबल नदी को पैदल पार करते समय डूब गये थे।**

सर्च ऑपरेशन में मृतका अलोपा बाई, रश्मि और रुकमणी का शव चंबल से निकाला गया। लेकिन बृजमोहन और लव कुश के शव नहीं मिले।

सोमवार सुबह एक बार फिर जगडरपुरा गांव में एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम, स्थानीय लोग और गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जगडरपुरा में चंबल नदी में चल रहे सर्च ऑपरेशन में एसडीएम, तहसीलदार, मंडरायल थाना अधिकारी सहित पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहें। सोमवार को नदी से पदयात्री लवकुश पुत्र थानसिंह एवं बृजमोहन पुत्र पप्पू, का शव निकाला गया। ज्ञात रहे कि, 17 पदयात्रियों का जत्था मध्यप्रदेश से कैलामाता के दर्शन के लिए आ रहा था जो, शनिवार को प्रात चंबल नदी पार करते समय हादसे का शिकार हो गया।

'बंद लिफाफों में इन्फॉर्मेशन देना बंद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया गया था। सी.जे.आई. ने भारत सरकार के सर्वोच्च वकील से कहा कि वे या तो इसे पढ़े या फिर वापस ले जायें।

न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने कहा, "हम गोपनीय दस्तावेज़ या सीलबंद लिफाफे नहीं लेंगे तथा मैं व्यक्तिगत रूप से इस (व्यवस्था) के खिलाफ हूँ। अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिये। यह (लिफाफा) आदेशों को लागू करने के विषय में हैं। इसमें गोपनीयता की क्या बात है?" उन्होंने कहा कि वे "सीलबंद लिफाफा व्यवस्था" को समाप्त करना चाहते हैं।

उन्होंने एटॉर्नी जनरल से कहा, "अगर सर्वोच्च न्यायालय इस (प्रथा) का अनुसरण करेगा, तो उच्च न्यायालय भी इसका अनुसरण करेंगे।"

मुख्य न्यायाधीश ने सीलबंद लिफाफों को एक बार पुन: "निर्धारित न्यायिक सिद्धांतों के पूरी तरह विरूद्ध" बताया।

उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, "इसका सहारा केवल तभी लिया जा सकता है, जब यह किसी व्यक्ति के जीवन के लिये खतरा बना रहे स्रोत या सूत्र के बारे में हो।"

इस केस (ओ.आर.ओ.पी.) के बारे में उन्होंने कहा कि अदालत पूर्व सैनिकों को ओ.आर.ओ.पी. एरियर्स के भुगतान से संबंधित सरकार की कठिनाई को समझ रही है लेकिन वह सरकार की कार्य-योजना की जानकारी चाहती है।

इसके बाद एटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट पढ़कर सुना दी।

उन्होंने पढ़कर सुनाया, "बजट इतनी बड़ी राशि एकमुश्त देने की स्थिति में नहीं है। संसाधन सीमित है तथा खर्चों को नियंत्रित करना जरुरी है। वित्त मंत्रालय ने विश्वास में लेने की कोशिश की गई थी किन्तु उसका कहना है कि इतनी बड़ी राशि एकमुश्त देने की स्थिति में नहीं है।"

मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की बैंच इस समय ओ.आर.ओ.पी. की बकाया राशि के भुगतान के लिये इंडियन एक्स-सर्विसमैन मूवमैन्ट्स (आई.ई.एस.एम.) की याचिका की सुनवाई कर रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 13 मार्च को सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुये कहा था कि उसने ओ.आर.ओ.पी. की बकाया राशि को चार किश्तों में अदा करने का "एकपक्षीय" निर्णय कैसे ले लिया।

रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक हलफनामा तथा एक अनुपालना रिपोर्ट अदालत में पेश की है तथा उसमें पूर्व सैनिकों को 2019 से 2022 तक के एरियर्स के 28,000 करोड़ रू. के भुगतान का सुनिश्चित बताया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिकों को ओ.आर.ओ.पी. एरियर्स का टुकड़ों में भुगतान करने के लिये 28 फरवरी, 2024 तक का समय दे दिया क्योंकि केन्द्र ने कहा था कि 28,000 करोड़ रू. की राशि का एकमुश्त भुगतान करने से रक्षा-प्रबंधन पर गंभीर असर पड़ सकता है।

अदालत ने आदेश जारी कर दिये कि 2019 के बाद के एरियर्स, फैमिली पेंशन पाने वालों तथा गैलेन्ट्री पुरस्कार विजेताओं (कुल 6 लाख लोग) को 30 मार्च तक, 70 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिकों (करीब 4 लाख) को 30 जून तक तथा शेष (10-11 लाख) को 31 अगस्त, 30 नवम्बर तथा 28 फरवरी तक दे दिये जायेंगे।

सी.जे.आई. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा कि यद्यपि बैंच इस बात से नाराज थी कि रक्षा मंत्रालय ने ओ.आर.ओ.पी. एरियर्स का भुगतान चार किश्तों में करने का एकपक्षीय निर्णय लेते हुये, सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय की अनदेखी कर दी थी कि भुगतान 15 मार्च तक कर दिया जाये, लेकिन अदालत सरकार की मुश्किलों को देखते हुये, यह महसूस करती है कि राष्ट्रहित की अनदेखी नहीं की जाये।

दिल्ली में किसानों...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर्ज़-माफी तथा पेंशन शामिल हैं, पूरी नहीं की तो एक और आंदोलन शुरु किया जायेगा।

इस विरोध-प्रदर्शन का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) ने किया था। ज्ञातव्य है कि एस.के.एम. ने ही दिल्ली की सीमाओं पर एक साल तक धरना देकर सरकार को तीन किसान-विरोधी कानून वापस लेने के लिये मजबूर कर दिया था। दोपहर बाद, एस.के.एम. के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट की तथा उन्हें अपना माँग-पत्र (चार्टर ऑफ डिमान्ड) सौंप दिया तथा उन्हें चेतावनी भी दी कि वे किसानों को एक और आंदोलन शुरु करने के लिए बाध्य न करें। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा, "ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका "समाधान नहीं हुआ है" तथा ये मुद्दे एक और "आंदोलन" की माँग कर रहे हैं। हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और मीटिंग आयोजित करेंगे। मैं सभी किसान यूनियनों से कहना चाहूँगा कि वे इस मीटिंग से पहले अपने-अपने राज्यों में रैलियाँ तथा पंचायतें करें।" उन्होंने कहा, "हम आये दिन आंदोलन करना नहीं चाहते। अगर सरकार हमारी माँगों पर ध्यान नहीं देगी, तो हम एक और आंदोलन करेंगे, जो कृषि कानूनों के विरोध में किये गये आंदोलन से कहीं बड़ा होगा।"

'चीन के "नैटिज़न" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उपनाम किया जाना दुर्लभ है। स्पष्ट रूप से उन्होंने चीन की जनता पर अपनी एक छाप छोड़ दी है।"

क्यू के अनुसार दोनों देशों के सीमा विवाद पर चीन के सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले लोगों ने कठोर और आक्रोशित प्रतिक्रियाएं दी हैं। उनकी धारणा यह है कि भारत ने पश्चिमी देशों का समर्थन लेकर और उसी उद्देश्य से "क्वाड" में शामिल होकर चीन की घेराबंदी कर उसे नियंत्रित कर लिया है।

वह दोनों देशों के मीडिया को एक सलाह देना चाहते हैं, वह यह की चीन और भारत के मीडिया को संयम बरतने की जरूरत है और भारत की एक आधुनिक एवं उदार छवि पेश करनी है ताकि चीन के सामान्य नागरिक को भारत की एक बेहतर छवि प्रस्तुत की जा सके।

यह भारत-चीन संबंधों के लिए निश्चित रूप से सार्थक होगा।

लेख में आगे कहा गया है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध, जिसने अमेरिका और पश्चिमी देशों को रूस के विरूद्ध खड़ा कर दिया है, चीन के अधिकांश लोग ऐसा महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का भारत विश्व के बड़े देशों के बीच एक संतुलन स्थापित कर सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ना केवल चीन के इन्टरनैट बल्कि चीन में भी लोकप्रिय हैं। मोदी ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट "सायना वेइबो" के अपने अकाउन्ट के माध्यम से चीन के जनता से भी बातचीत की थी।

यह अकाउन्ट उन्होंने वर्ष 2015 में खोला था और उनके 2.44 लाख से अधिक फोलोअर्स थे। हालांकि सीमा पर हुई झड़प के बाद भारत सरकार ने जब चीन के 59 ऐप्स प्रतिबंधित किए, तब उन्होंने जुलाई 2020 में स्वयं को वेइबो से हटा लिया था। ट्विटर के समकक्ष माने जाने वाले चीन के सिना वेबो के वर्तमान में 582 मिलियन से अधिक एक्टिव यूज़र्स हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2014 में केन्द्र में पहली बार सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिन्पिंग की अहमदाबाद में मेजबानी की थी और उनके बाद चीन के पूर्व प्रमुख ली केकियांग की।

द डिप्लोमैट का लेख आगे कहता है कि भारत को लेकर चीन के लोगों के विचार काफी जटिल हैं, लेकिन इसका आधार वर्चस्व और आत्म-विश्वास की भावना है।

लेख यह भी उल्लेख करता है कि चीन के सोशल मीडिया यूज़र्स की राय में पाकिस्तान की अपेक्षा भारत के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए क्योंकि उनका मानना है कि अपने सुख-दु:ख के साथी पाकिस्तान का इस्तेमाल करने के चीन के प्रयास अवास्तविक हैं क्योंकि दक्षिण एशिया के दोनों पड़ोसी देशों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है।" पाकिस्तान पिछले कुछ समय से राजनीतिक और आर्थिक बदहाली झेल रहा है।

लेख में कहा गया है कि "पिछले नौ वर्षों के तथ्यों से यह साबित हुआ है कि चीन और भारत के बीच सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के साथ चीन का व्यापार 115 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष है, जो पाकिस्तान के साथ उसके व्यापार 30 बिलियन डॉलर से कहीं अधिक है।

लेख में, पश्चिमी देशों के साथ भारत की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर चीन की आशंकाओं का भी उल्लेख है, खासतौर पर अमेरिका के साथ और जहां तक यूक्रेन संकट का प्रश्न है, नई दिल्ली और बीजिंग के विचार मिलते-जुलते हैं।

लेख में आगे बताया गया है कि चीन के सोशल मीडिया यूज़र्स में प्राय: एक ही बात को लेकर चर्चा है कि "भारत पश्चिमी देशों का फेवरेट क्यों है", जबकि चीन पश्चिमी जगत का निशाना बन चुका है। भारत ने यह सब कुछ कैसे किया?

इसका उत्तर यह है कि चीन के अधिकांश लोग वर्चस्व और आत्मविश्वास की भावना से ऐसा महसूस करते हैं कि भारत चीन की अपेक्षा इतना विकसित नहीं हुआ है कि वह पश्चिमी देशों के लिए खतरा बन सके।

'लिव इन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथा न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा एवं जे.बी. पारदीवाला की बैंच ने जानना चाहा कि क्या याचिकाकर्ता उन्हें संरक्षण देने के बहाने, लिव-इन- रिलेशनशिप को रोकना चाहते हैं। इस बात पर खिन्नता व्यक्त करते हुये कि "लोग कुछ भी लेकर" सर्वोच्च न्यायालय चले आते हैं, सी.जे.आई. चन्द्रचूड़ ने पूछा, "रजिस्ट्रेशन किसके साथ? केन्द्र सरकार के साथ? केन्द्र सरकार को लिव-इन-रिलेशनशिप्स में रह रहे लोगों से क्या लेना-देना?" उन्होंने इस याचिका को खारिज करने से पहले कहा, "हम इस प्रकार के केसों पर जुर्माना करना शुरु कर देंगे। उन्होंने इसे, "मात्र एक अविवेकपूर्ण याचिका" कहते हुये, खारिज कर दिया। एडवोकेट ममता रानी ने मांग की कि केन्द्र को निर्देश दिये जायें कि वह लिव-इन- रिलेशनशिप के लिये नियम बनाये। उन्होंने दलील दी कि अदालत ने लिव-इन-रिलेशनशिप के सदस्यों को कई बार संरक्षण प्रदान किया है, "चाहे वे महिलाएं हों, पुरुष हों, या इस प्रकार सम्बंध से जन्में बच्चे हों।"

सिलिकॉन वैली बैंक को डूबने से बचाने के....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रवैया नहीं रखा बल्कि उन्होंने इसे तुरन्त सहायता प्रदान कर लाइफ लाइन दी। बैंक को डूबने से बचाने के लिए यह एक त्वरित कदम था।

उन्होंने ऐसा क्या किया? अमेरिकी सरकार ने यह आश्वस्त करने के लिए हस्तक्षेप किया कि संकटग्रस्त बैंक के सभी जमाकर्ताओं को अगले सोमवार से अपने फण्ड्स पर पूरा एक्सैस मिलेगा। यह फैडरल इश्योरैं कॉरपोरेशन (एफ.डी.आई.सी.) की डिपॉज़िट इंश्योरैंस कवर्स की सीमा से अधिक था। कॉरपोरेशन अब तक 2 लाख 50 हजार डॉलर्स तक के डिपॉज़िट पर इंश्योरैंस कवर दे रहा था।

तुरन्त प्रभाव से जारी किए गए एक कार्यकारी आदेश से यह सीमा बढ़ाई गई और कहा गया कि सारी जमा राशि का पुनर्भगतान होगा। ऐसी स्थिति में जबकि सरकार जमाकर्ताओं के फण्ड्स के लिए आश्वासन दे रही हो, जमाकर्ताओं को अपने फण्ड्स ना निकालने को लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है।

यह पर्याप्त है। अमेरिका के केन्द्रीय बैंक ने इसके बाद एक उपाय की घोषणा की जिसके और व्यापक प्रभाव रहे होंगे।

दूसरा उपाय यह घोषित किया गया कि यू.एस. फैडरल रिज़र्व अंतिम उपाये के रूप में संकट में फंसे बैंक को अमेरिकी बॉण्ड्स के लिए उनकी फेस वैल्यू के आधार पर फण्ड्स उधार देगा। यह बैंकों की नाज़ुक स्थिति और उनके सुनियोजित जोखिम के मूल कारण को हल करना है।

वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद केन्द्रीय बैंकों ने बहुत सस्ती दर पर पैसा उपलब्ध करवाया था लेकिन बैंकों ने यह पैसा अच्छी ब्याज दर पर उधार देने के बजाय सरकारी बॉण्ड खरीद लिए।

जब वित्तीय नीतियां सामान्य होने लगीं ब्याज दर बढ़ने लगी इन बॉण्ड्स का बाज़ार मूल्य घट गया। इसलिए जरूरत पड़ने पर बैंकों को कम दर पर बॉण्ड बेचने पड़े जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। इन हालात में बैंकों की पूँजी घट गई और वित्तीय क्षमता कमजोर हो गई। यह ही स्थिति है जब बैंक फेल हो जाता है

बड़े बैंक के डूबने की शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है और इसका प्रभाव अन्य बैंकों व समूचे फाइनैशियल सिस्टम पर पड़ता है। लेकिन तब एस.वी.बी. इतना भी बड़ा और महत्वपूर्ण नहीं था कि इसे डूबने न दिया जाए! तो फिर इसे क्यों बचाया गया?

यह इसलिए किया गया क्योंकि एस.वी.बी. एक विशिष्ट बैंक है और इसका संबंध अमेरिका की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सैक्टर से है। इसने सिलिकॉन वैली में अमेरिका के टैक्नॉजिकल उद्योग को पाला-पोसा है। आई.टी. सैक्टर की अधिकांश कंपनियों का लेन-देन एस.वी.बी. से ही होता है। एस.वी.बी. के डूबने से इनका पैसा फंस गया है जिससे उनके लिए स्टाफ को वेतन देना भी भारी पड़ सकता है।

सिलिकॉन वैली के इको सिस्टम को बचाने के लिए बैंक को बचाना आवश्यक है जैसा कि लैरी समर्स ने इकोनॉमिस्ट पत्रिका के साथ वार्ता में कहा। दूसरे, जैसा उन्होंने महसूस किया कि यह 21वीं सदी का संक्रमण बन सकता है और इसे रोकना होगा। एक असफलता का असर बहुतों पर पड़ सकता है।

एस.वी.बी. के बाद अमेरिका के एक और बैंक पर ऐसा ही खतरा आया था पर एक अन्य ऑपरेटर ने बैंक को टेक ओवर कर खतरा टाल दिया।

अटलांटिक के पर यूरोपियन बैंकिग का एक प्रतिष्ठित नाम है "क्रेडिट स्वीस"। इसके समक्ष भी डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया था पर स्विस सैंट्रल बैंक तुरंत इसके बचाव में आगे आया। बाद में एक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बैंक यू.बी.एस. ने इसका अधिग्रहण कर लिया।

ये सभी घटनाएं भारतीय नीति निर्माताओं व इस क्षेत्र के विचारकों के लिए एक सबक हैं। वित्तीय समझ और संस्थापन की आर्थिक परम्पराओं का अनुसरण करते हुए एक वित्त मंत्री ने फिस्कल प्रूडेस एक्ट के उद्देश्यों को पाने के लिए गंभीर वित्तीय संकुचन की शुरुआत की। वित्तीय अवरोध इतना कठिन था कि अर्थव्यवस्था मानो चीत्कार कर उठी हो।

वित्त मंत्रालय ने निर्धारित किया है कि अगर कोई बैंक बंद होने की स्थिति में हो तो उसमें पैसा जमा करने वालों को बीमा नियमों की सीमा के तहत ही हर्जाना दिया जाएगा, जिससे बैंक में पैसा जमा करने वालों में आशा की लहर दौड़ गई कि अगर बैक डूबे या इसका विलय हो तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ये आम जनता व बचत कर्ताओं के लिए दंडात्मक प्रावधान है। एक बैंक पर भरोसा करने से उनकी जीवन भर की जमा पूँजी छिन सकती है वो भी गलती के बिना।

वित्तीय सैक्टर की विश्वसनीयता एक देश और अर्थव्यवस्था की नींव होती है। एक ऐसे देश जहाँ सोशल सिक्योरिटी नैटवर्क नहीं होता है वहाँ बैंकों में जमा राशि ही जीने का आखिरी सहारा होती है।

इस देश में सरकार को जमाकर्ताओं को सुरक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। कम से कम सरकारी बैंको में तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। इससे जमाकर्ता का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

'अभी तक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक मुख्य प्रश्न, सचिन पायलट व अजय माकन द्वारा बार-बार पूछा जा रहा है कि, अब तक सी.एल.पी. मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई है, जबकि छ: महीने बीत गए हैं।

सचिन पायलट न्यूज़ 18 कॉन्कलेव में आमंत्रित अतिथि थे, जहाँ उनसे राजस्थान तथा राज्य के आगामी चुनावों के बारे में कई प्रश्न पूछे गए।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2